ऊर्जा उत्पादन केंद्र लगाएंगे। इसे

एमएसएमई सेक्टर में 82 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव

70 हजार करोड़ लागत वाले 5 हजार से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के तहत अब तक 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें 70 हजार करोड़ रुपये की लागत वाले उत्पादों के लिए सम्मझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। इन एमओयू के माध्यम से प्रदेश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 15 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अब तक सात हजार से अधिक एमओयू हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक पांच हजार से अधिक एमओयू एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किए गए हैं। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई एमएसएमई नीति भी मंजूरी की गई है।

एमएसएमई विभाग को राज्य सरकार ने 1.25 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य दिया था। विभाग 5700 से ज्यादा निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल रहा है। इन प्रस्तावों की कुल कीमत 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें 70 हजार करोड़ से अधिक के 5300 से अधिक एमओयू किए जा हो चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 56 प्रतिशत है। 300 से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को एमओयू तक लाने का प्रयास चल रहा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन किए जा रहे हैं। निदेशालय की ओर से लैंड बैंक डाटा भी तैयार किया गया है। एमएसएमई नीति के तहत आनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली तैयार की जा रही है।

10 जनवरी तक प्राप्त आंकड़ों में एमएसएमई के अंतर्गत प्रदेश सरकार को जो एमओयू प्राप्त हुए हैं, उनमें 15 प्रतिशत एमओयू ऐसे हैं जिनकी कुल कीमत 25 करोड़ से 50 करोड़ रुपये के बीच है, जबकि 13 प्रतिशत एमओयू ऐसे हैं, जिनकी कुल कीमत 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपये के बीच है। 30 प्रतिशत एमओयू पांच से 10 करोड़ रुपये के मध्य के हैं। सर्वाधिक 42 प्रतिशत एमओयू पांच करोड़ रुपये से कम लागत वाले हैं।

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

15 लाख से अधिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को

दस जनवरी तक इन जिलों में हुए सर्वाधिक एमओयू

जिला	निवेश के लिए हुए एमओयू
गाजियाबाद	9080 करोड़ रुपये
मुरादाबाद	7815 करोड़ रुपये
गौतमबुद्धनगर	5821 करोड़ रुपये
मेरठ	4775 करोड़ रुपये
कानपुर देहात	4229 करोड़ रुपये
वाराणसी	3191 करोड़ रुपये
अलीगढ़	2768 करोड़ रुपये
लखनऊ	2760 करोड़ रुपये
हापुड़	2310 करोड़ रुपये
बुलंदशहर	1933 करोड़ रुपये

आबकारी में भी 22,821 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

ग्लोबल इन्वेस्ट समिट से पूर्व आबकारी विभाग भी निवेश के प्रस्तावों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब तक 22,821 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि आसवनी, यवासवनी, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों पर उद्योग स्थापित किये जाने के लिए 17 निवेशकों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें लगभग 16,392 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। दो निवेशकों ने पोर्टल के माध्यम से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 1400 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। पोर्टल पर कुल 17,792 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अपर मुख्य सचिव ने निवेशकों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसमें 43 निवेशकों ने प्रतिभाग किया । इनमें 16 निवेशकों ने लगभग 5,029 करोड़ रुपये के निवेश के लिए तत्काल प्रोफार्मा भरकर उपलब्ध कराया। इस तरह अब तक लगभग 22,821 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।

सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 7,849 करोड़ का निवेश प्रस्ताव

- पैक्स के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में होंगे कार्य
- फरवरी तक माडल बाईलाज को अंगीकार कर लेगी राज्य सरकार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 7,849.55 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समिति (बी-पैक्स) या लार्ज एरिया मल्टीपरपज सोसायटी (लैम्प्स) में परिवर्तित कर कार्य करने के लिए माडल बाईलाज निर्गत किए गए हैं।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में पैक्स के माध्यम से कार्य किए जा सकेंगे। माडल बाईलाज से पैक्स समितियों को व्यावसायिक विविधीकरण, अपने कार्यक्षेत्र के बाहर विपणन व सामान्य कार्य संपन्न करने, कामन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने, एफपीओ का संवर्धन व आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पीपी माडल पर कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गई है।

राठौर ने बताया कि समिट में सहकारिता विभाग के माध्यम से 7500 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी तुलना में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 13 जनवरी तक नैनो उर्वरक उत्पादन प्लांट के लिए 638.00 करोड़ रुपये, शुगर एवं एथेनाल सेक्टर में 710 करोड़ रुपये, भंडारण व पोस्ट हारवेस्ट सुविधाओं तथा शीत गृहों के लिए 5305.85 करोड़ रुपये, पेट्रोल पंप व सीएनजी स्टेशन के लिए 1050.00 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य व शिक्षा क्षेत्र में 145.70 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 7849.55 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे लगभग 12561 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

राठौर ने बताया कि माडल बाईलाज के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में अब कार्य पैक्स के माध्यम से किए जा सकेंगे। प्रदेश में भारत सरकार के माडल बाईलाज के अंगीकरण की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है, जो फरवरी माह तक पूर्ण हो जाएगी।

मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ समिति के सदस्यों व किसानों का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सकेगा।